due to landslides and rain. The State Government of Meghalaya, with its limited resources, is trying hard to ameliorate the conditions of the people affected by this catastrophe but the State Government is cash-strapped to cope with the extent and intensity of disaster.

I, therefore, request the Central Government to provide sufficient financial assistance to the State Government so that the lives of the people affected by the disaster can be normalized.

Concern over the incident of beheading Indian soldiers by Pakistani soldiers in Kupwara District on Indo-Pak border

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब)ः महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ की नई घृणित घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। जुलाई, 2011 के आखिरी सप्ताह में कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। उनकी मुठभेड़ उस समय-सीमा पर गश्त कर रही कुमाऊं रेजीमेंट तथा 19 राजपूत बटालियन के सैनिकों से हुई। मुठभेड़ के दौरान कुमाऊं रेजीमेंट के दो जवान तथा 19 राजपूत बटालियन का एक जवान शहीद हुआ। कुमाऊं रेजीमेंट के जवानों की पहचान हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी तथा लांस नायक देवेन्द्र सिंह के रूप में हुई तथा राजपूत बटालियन के जवान की अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

महोदय, कुमाऊं रेजीमेंट के दोनों शहीदों के सिर पाकिस्तान के सैनिकों की आड़ में आतंकवादियों द्वारा काट लिए गए और वे उनको पाकिस्तान ले गए। उनके शरीर के शेष भाग को इस प्रकार रौंदा गया था कि उनके परिवारों को भी उनका मृत शरीर नहीं दिखाया गया और कहा गया कि बम फटने से सिर उड़ गए हैं। यह घटना जिस समय पाकिस्तान की विदेश मंत्री हीना रब्बानी भारत दौरे पर थी, उस समय की है।

मेरी सरकार से मांग है कि उक्त मामले पर पाकिस्तान की सरकार को कड़ा उत्तर देना चाहिए और सीमा पार से पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों का यथोचित जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री कांजीभाई पटेल (गुजरात)ः महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़)ः महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा)ः महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

Demand to take steps for rehabilitation of slum dwellers in cities of the country

श्री परिमल नथवानी (झारखंड)ः महोदय, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और रांची जैसे देश के महानगरों में स्लम बस्तियों की समस्या आम बात है। इन बस्तियों में बाकायदा बिजली, पानी आदि की सुविधा होती है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन बस्तियों को उजाड़ा तो नहीं जा सकता। मार्च, 2011 में झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के कथित आदेश के बहाने रांची सहित कतिपय नगरों में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के नाम पर गरीबों की बसी-बसाई बस्तियां उजाड़ दीं। न्यायालय के आदेश में विशाल भवनों, होटलों व स्टोरों द्वारा अतिक्रमण हटाने की बात थी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने कुछ खास बस्तियों को लक्ष्य बनाया।